LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, April 19, 1982/ Chaitra 29, 1904 (Saka):

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Utilization of Services of Local Research Institutions for Forest Products

†

*755. SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY:
SHRI RAJESH PILOT:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps to utilize the services of the departments of botany and zoology of local educational and research institutions for preservation, development and utilization of forest products;

(b) if so, with what results; and

(c) if not, reasons for such non-utilization?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Yes, Sir. A scheme for funding research through Universities was started in the Fifth Plan and is continuing in the Sixth Plan programme of the Forest Research Institute and Colleges.

(b) The schemes are in progress and the results are awaited.

(c) Does not arise.

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY: Sir, I did not ask about the research through various Forest research Institutes. My question is very simple. I wanted to know about the utilisation of the services of various departments of botany and zoology of the local educational and research Institutes. This point has not been answered. Secondly, they have taken up a scheme for funding research through the universities during the Fifth Plan and it is being continued in the Sixth Plan also. I would like to know from the hon. Minister the amounts allocated for this purpose how much was spent so far and on what items of work?

SHRI R. V. SWAMINATHAN: In the Colleges and the Forest Research Institutes a scheme for funding research has already been included in the Sixth Plan. As far as the amount is concerned, I may inform the hon. Member that in the Sixth Plan, the outlay for this scheme is Rs. 30 lakhs. But so far we have spent about Rs. 17 lakhs.

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY: Actually, various research schemes always remain on paper only, and there is no coordination between the Department of Forest and local research and the educational institutions. I would like to know from the hon. Minister, whether there is any scheme to revise the syllabus relating to the actual problems, so that some pilot research projects can be taken up and their practical utility evaluated.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: Such schemes are being taken up at the

Calcutta University, Bhopal University, Utkal University, Osmania University, Visva-Bharti University and Punjab Agricultural University, Ludhiana. Therefore, such things are being taken up regularly.

MR. SPEAKER: Shri Rajesh Pilot. He was saying that such schemes remain on the paper. Can you make them fly in the air?

SHRI RAJESH PILOT: Our Prime Minister has been laying emphasis on the linking of education with development and employment, and has also been insisting upon the awareness to be created about the environment and public initiative and involvement in preserving the natural wealth and exploiting new resources of nature, but unfortunately, the appeal has not percolated from the bureaucratic channel and hence the present state of affairs. May I know from the hon. Minister whether the Government have reoriented the teaching in the Universities in subject like zoology and botany to make them relevant to the local problems of forest and forest yield and also associate the local Forest Department to the teaching in these subjects?

Further, has the Government considered the question of using the youth of the country in schools and colleges in preventing indiscriminate deforestation as it is done in certain countries like British Columbia and Canada?

SHRI R. V. SWAMINATHAN: The forest product research comprises of timber mechanics, timber engineering etc. The hon. Member wants to know whether the research is oriented to meet the needs of the country. For that, we have got a proposal for creating a Central Forestry Research Service in the Agricultural Universities.

SHRI RAJESH PILOT: What about using the youth for this?

SHRI R. V. SWAMINATHAN: We are using them.

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खास कर के जो पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोग रहते हैं जिनका जंगल से बहुत लगाव रहता है, और बहुत सारे हमारे कालेज खुले हुए हैं तो जो इसमें इंटरैस्ट रखने वाले कालेज हैं उनमें क्या इस सबजेक्ट को कम्पलसरी करेंगे ? और जैसा माननीय सदस्य ने कैलीफोरनिया का हवाला दिया क्या आप भी भारत में ऐसी यूनीवर्सिटी बनाएंगे जो खास तौर से फौरेस्ट के बारे में ही शिक्षा दे और जिस प्रकार आज जंगल उजड़ रहे हैं और जलवायु खराब हो रही है उसको रोका जाय । इस बारे में आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह): फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, फोरेस्ट कालेज, रिसर्च कालेज, देहरादून में है । इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंटस को भी हम ऐनकरेज कर रहे हैं कि फोरेस्ट कालेजेज़ और जितने भी खोलना चाहें स्टेट्स के अन्दर खोलें साथ ही साथ सोच रहे हैं कि फोरेस्ट्री ऐजूकेशन सिर्फ सर्विस के लोगों के लिये ही न हो, इनसर्विस ट्रेनिंग खाली मकसद उसका न हो, बल्कि और लोग भी फोरेस्ट्री पढ़ना चाहें तो उसकी फैसेलिटी होनी चाहिए । यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग अपना सिलेबस है । अलग अलग कोर्सेज़ आफ स्टडी हैं, उसके अन्दर फोरेस्ट को भी काफी इम्पोर्टेंस मिलती है और उस चीज की तरफ़ भी ध्यान दिया जा रहा है ।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि 70 लाख रु० की राशि अभी तक वनों के अनुरक्षण और विकास पर व्यय हुई है । और उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के लिए भोपाल, और लुधियाना ऐग्रीकल्चर यूनि-

वर्सिटीज का चयन किया गया था । तो छोटानागपुर में घना जंगल है और जिसका देश में महत्व है क्या उसके लिए भी कोई योजना बनाई गई है या कोई फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां कायम करने का सरकार विचार कर रही है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : 70 लाख नहीं 30 लाख रु० की राशि मेरे साथी ने बतायी थी । छठी प्लान में इस स्कीम पर 30 लाँख रु० रखा गया है जिसमें से 17 लाख पहले ही खर्च कर दिया गया है । जिन यूनिवर्सिटीज़ में यह काम हो रहा है, उनके नाम उन्होंने बताये हैं । कोई और यूनिवर्सिटीज अगर कोई प्रोजेक्ट बनाकर हमारे पास भेजेंगी तो उस पर भी गौर किया जायेगा ।

Planning at Village Level

*756. SHRI PIUS TIRKEY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whethr Government have received any suggestion from Extension Education Association, having its headquarters in Indian Agricultural Research Institute, with regard to the planning at the village level; and

(b) if so, action taken in this respect?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) No, Sir. So far Indian Society of Extension Education has not sent any recommendation to the Government with regard to planning at the village level.

(b) Question does not arise.

श्री पीयूष तिरकी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि प्रधान मंत्री ने 15 अप्रैल, 1982 को इन्नोवेशन टेक्नोलाजीज़ फार इन्टेग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट को सतर्क करते हुए कहा कि ग्राम यूनियन परिकल्पना के काम संतोषजनक नहीं है । चौथी पंचवर्षीय योजना में जो परिकल्पना की गई थी, वह जिला स्तर पर की गई थीं और जिला स्तर से उपर जो ग्रामों के लिये योजनाएं बनाई जाती थीं, वह उचित साबित नहीं हुई और उनमें लाभ के बदले हानि हुई ? छठी पंजवर्षीय योजना में भी प्लानिंग को नीचे, डिसैंट्रलाईजेशन आफ प्लानिंग प्रासेस टू दी ब्लाक लैवल की बात कही गई है । जनता सरकार ने 1978–79 में यहां तक कहा था कि 10 वर्ष में सभी लोगों के लिए लाभजनक काम संस्थान की व्यवस्था की जायेगी । इसके पश्चात् सरकार में बदली होने के बाद भी 1980 में वर्तमान सरकार ने आश्वासन दिया, करार किया कि माइक्रो लैवल प्लान फार इरैडिकेशन आफ पावर्टी पर जोर दिया जायेगा और ब्लाक लैवल पर स्कीम बनाई जायेगी । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कही गई बात सच है या नहीं ? यदि सच है, तो इस संबंध में डिसैंट्रलाइजेशन आफ प्लानिंग करने में उनको कौनसी आपत्ति है ? वहां की उन्नति के लिए लोक लैवल से जो समितियों से प्लान भेजी जायेंगी उनको सरकार स्वीकार करेगी या नहीं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : गवर्नमेंट की पालिसी यही है कि प्लानिंग जहां तक हो सके नीचे के लैवल पर होनी चाहिए । इस चीज को ध्यान में रखते हुए जितने हमारे एन आर ई पी के प्रोग्राम हैं, उनको सारी प्लानिंग पंचायत लेबल पर होती है ब्लाक लैवल पर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डैवलपमेंट के लिए हमारे पास स्कीम हैं, उसमें 50 परसेंट स्ट्रैन्थन करने के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से सबसीडीज और ग्रांट्स दी जाती हैं । बहुत